

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2022—फाल्गुन 6, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री गोविन्दराम चुरेन्द्र, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 1-01/2022/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री दिलराज प्रभाकर, भा.व.से. (2008)	वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल.	वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल.
2.	श्री संजय यादव, भा.व.से. (2015)	वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल.	कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर.
3.	श्री चूडामणि सिंह, भा.व.से.	उपवनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल.	वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल.

2. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 1-02/2020/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय वन सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान प्राप्त उप वन संरक्षक संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान (Super Time Scale (i) : Level 13A in the Pay Matrik Rs. 1,31,100-2,16,600) में पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. श्री राजेश कुमार चंदेले (2003)
2. श्रीमती एम. मर्सीबेला (2007)
3. श्री मनोज कुमार पाण्डेय (2007)
4. श्री अमिताभ बाजपेयी (2007)
5. श्री राम अवतार दुबे (2007)

उक्त आदेश दिनांक 31-12-2021 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 1-13/2021/11/6.—विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24-12-2021 की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद्वारा पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़ की स्थापना में कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (वेतनबैंड रु. 9300-34800+ग्रेड पे 4200/-) को सहायक पंजीयक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे 5400/-)

स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक उनके नाम के सामने कॉलम (4) में दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना स्थल (3)	नवीन पदस्थापना स्थल (4)
1.	श्री प्रमोद कुमार कुजूर	निरीक्षक, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, छ.ग.	सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं दुर्ग संभाग, दुर्ग.
2.	श्रीमती अनुपमा कुजूर	निरीक्षक, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, छ.ग.	सहायक पंजीयक कार्यालय पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं रायपुर.
3.	श्री सतीश कुमार शर्मा	निरीक्षक, सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, बिलासपुर संभाग.	सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बस्तर संभाग, जगदलपुर.

2. उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों में से यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी की वरिष्ठता अथवा न्यायालयीन प्रकरण में पदोन्नति की पात्रता के संबंध में भविष्य में कोई निर्णय/आदेश होता है तो संबंधित अधिकारी को पद अभाव के कारण पूर्व पद पर पदावनत कर दिया जायेगा.

3. उक्त पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका W.P.(S) No. 9778/2019 एवं WP (PIL) No. 91/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णय के अध्याधीन होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 6-55/2021/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-12-2021 के परिप्रेक्ष्य में, राज्य कर सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	कु. सुषमा लाल	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-1.	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, बिलासपुर संभाग-दो.
2.	श्री हर्षित मिश्रा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-1.	अतिरिक्त राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-चार.
3.	श्री सौरभ बासु	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-8.	अतिरिक्त राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-तीन.
4.	कु. दीप्ति मिश्रा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-2.	राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-एक.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री गोपाल दास मानिकपुरी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-5.	कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय, नवा रायपुर.
6.	श्री मनोज चंदेल	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-2.	अतिरिक्त राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-तीन.
7.	कु. श्वेता चंद्राकर	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-6.	अतिरिक्त राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-छः
8.	श्रीमती श्रद्धा सुमन वर्मा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-3.	प्रभारी, राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-दो.
9.	श्री सुरेन्द्र पटेल	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-9.	प्रभारी, राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-पांच.
10.	कु. रश्मि साहू	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-1.	अतिरिक्त राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-एक.
11.	कु. रिंकी जंधेल	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-9.	अतिरिक्त राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-एक.
12.	श्री आनंद कुमार डोंगरे	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-7.	प्रभारी, राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-दो.
13.	श्री शैलेन्द्र पाटले	प्रतिनियुक्ति पर संचालनालय, नगरीय प्रशासन विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर.	राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त-एक.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 6-48/2020/वाक/पांच.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2020 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग में राज्य कर सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्य सूची में अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, तीन वर्ष की परीक्षा पर राज्य कर सहायक आयुक्त के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 5400) में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उनकी पदस्थापना राज्य कर सहायक आयुक्त (परीवीक्षाधीन) के रूप में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये कार्यालय में की जाती है :—

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं स्थायी पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरण होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
.1.	1	श्री आभास सिंह ठाकुर पिता-श्री रामकृष्ण सिंह ठाकुर, ए/3, राजेन्द्र पार्क, न्यू पुरैना, पो.आ. रविग्राम, रायपुर (छ.ग.) पिनकोड-492006	अनारक्षित	कार्यालय, राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-आठ.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	2	श्री विजय कैवर्त, पिता-श्री कुलदीप कैवर्त, होलिका चौक देवागन मोहल्ला, लाला गली, वार्ड क्र. 08, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिनकोड-495330.	अ.पि.वर्ग	कार्यालय, राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त-एक.
3.	3	श्री वैभव कांत प्रधान, पिता-श्री लीलाधर प्रधान, S/o लीलाधर प्रधान, वैभव कुंज, प्रधानपारा, देवभोग, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) पिनकोड-493890.	अनु. जाति	कार्यालय, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, रायपुर संभाग क्रमांक-एक.
4.	4	सुश्री कीर्तिका राज, पिता-श्री मध्वेश्वर राज, ग्राम-बकसाही, पो.आ. बकसाही, तहसील-पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन कोड-495449.	अनु. जनजाति	कार्यालय, राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरबा वृत्त-दो.
5.	5	श्री जीतेश कुमार, पिता-श्री गिरवर सिंह, 141 ए/1 एन ए टाईप सड़क नंबर 20 टाउनशिप दल्लीराजहरा, थाना-दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.), पिनकोड-491228.	अनु. जनजाति	कार्यालय, राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-तीन.

2. उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

- (i) उपरोक्तानुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापपेण्ड देय होगा —
- | | | |
|--------------|---|--|
| प्रथम वर्ष | — | पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत |
| द्वितीय वर्ष | — | पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत |
| तृतीय वर्ष | — | पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत |

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टापपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.

- (ii) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा.

3. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी नियुक्ति उपरांत उपस्थित होने पर संलग्न प्रारूप (एक) में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे.

4. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

5. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

6. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण करनी होंगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. उक्त अधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण नहीं कर पाने अथवा उसे सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी. परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवाएँ परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न हो.

7. अभ्यर्थियों का निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी.
8. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2019” के प्रावधानों के तहत शासित होगा.
9. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय “मेडिकल बोर्ड” से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. “मेडिकल बोर्ड” द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.
10. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित राज्य कर संयुक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त के समक्ष मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.
11. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.
12. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते, प्रशिक्षण एवं यात्रा आदि व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.
13. चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.
14. “प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशों/प्रावधानों का पालन किया गया है.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, अवर सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 1-17/2014/धर्मस्व/छः.—राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजिम माघी पुन्नी मेला 2022 हेतु विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी 2022 में गठित केन्द्रीय समिति में निम्नलिखित सदस्यों को जोड़ता है :-

01	श्री चन्द्रलाल साहू, पूर्व सांसद महासमुंद	—	सदस्य
02	श्री जनक ध्रुव, जिला-गरियाबंद	—	सदस्य
03	श्री भावसिंह साहू, जिला-गरियाबंद	—	सदस्य
04	श्रीमती स्मृति ठाकुर, जिला-गरियाबंद	—	सदस्य

उक्त अधिसूचना के द्वारा गठित शेष समिति यथावत बना रहेगा.

No. F 1-17/2014/Dharmasva/Chh.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of section 3 of the Chhattisgarh Rajim Maghi punni Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006) the State Government hereby constituted in the Departmental Even number Notification Dated 19 January 2022 for central committee for Rajim maghi punni Mela years 2022 Adds the Following Members :—

01	Shri Chandulal Sahu, ex. Member of parliament	—	Member
02	Shri Janak Dhuru, Dist. Gariaband	—	Member
03	Shri Bhav Singh Sahu, Dist. Gariaband	—	Member
04	Smt. Smriti Thakur Dist. Gariaband	—	Member

Rest of the Committee Constituted by the said notification shall remain unchanged.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एमरेंसिया खेस्म, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्वारा चीफ कन्ट्रोलर ऑफ माइन्स, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-2 के बिन्दु क्रमांक-2 एवं पत्र दिनांक 21-09-2011 तथा भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08-10-2014 एवं खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम, 12 के अनुपालन में Differential Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए खनिज कोयला को छोड़कर समस्त खनिजों के खनिज रियायतों के सीमाओं में Precise Boundary Pillar की स्थापना कर सर्वेक्षण करने के लिए नीचे तालिका में दर्शित संस्थानों की अधिमाम्यता का नवीनीकरण प्रदान करता है :—

क्र. (1)	आवेदित एजेन्सी का नाम एवं पता (2)	पूर्व अधिमाम्यता अवधि (3)	रिमार्क (4)
01	मेसर्स सन सर्वे इंजीनियरिंग, रजिस्टर्ड कार्यालय: 465, जिन पाल बगान, करबला (पश्चिम), पो.आ. एवं जिला हूगली, पश्चिम बंगाल-712103	10-11-2017 से 09-11-2020 तक (03 वर्ष)	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
02	मेसर्स जियो सॉल्यूशन (प्रायवेट) लिमिटेड, HIG-21, हुडको कालोनी, आमदीनगर, भिलाई जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)	10-05-2018 से 09-05-2021 तक (03 वर्ष)	

उपर्युक्त तालिका के सरल क्रमांक-1 एवं 2 को क्रमशः विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-04-2018 द्वारा दिनांक 10-11-2017 से 03 वर्ष एवं अधिसूचना दिनांक 04-09-2018 द्वारा 03 वर्ष तक संस्थानों को डीजीपीएस सर्वे कार्य किये जाने हेतु सशर्त प्रदान की गई अधिमाम्यता का नवीनीकरण किया गया था जिसकी अवधि क्रमशः दिनांक 09-11-2020 एवं 09-05-2021 को समाप्त हो गई है. अतएव राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिमाम्यता का नवकरण सरल क्रमांक-1 के लिये दिनांक 09-11-2020 से एवं सरल क्रमांक-2 के लिये दिनांक 09-05-2021 से आगामी 03 वर्ष के लिये नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण प्रदान करता है.

2. अधिमाम्यता प्राप्त संस्थानों के लिए निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की गई हैं :—

1. Each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar).

2. There shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;
3. The distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;
4. The pillar shall be of square pyramidal frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;
5. Each pillar shall be of reinforced cement concrete;
6. The corner pillar shall have a base of $0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$ and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;
7. The intermediate pillars shall have a base of $0.25\text{m} \times 0.25\text{m}$ and height of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;
8. All pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimeters in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete.
9. On all corner pillars, distance and bearing to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked;
10. Each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillar;
11. The number of pillars shall be the numbers of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;
12. The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees.
13. The lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Control General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf.
14. The location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee: and
15. In case of forest area within the lease, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf.
16. The Survey Agency shall be responsible for the accuracy of the data collected during Survey.
17. Coordinates of boundary pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.
18. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.
19. डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरान्त राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.

20. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.
21. राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता केवल 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एंजेसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.
3. यह अधिमान्यता नवकरण अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 07-31/2021/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 18-10-2021 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित), 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (वर्गमीटर में)	रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में दर्शित भू उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर खास	905 का भाग	6082	मार्ग	आमोद-प्रमोद
		1943 का भाग	3144	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक जलाशय एवं मार्ग	आमोद-प्रमोद
		2035	6082	मार्ग	आमोद-प्रमोद

2. उक्त उपांतरण स्मार्ट सिटी के तहत बुढ़ातालाब क्षेत्र को व्यवस्थित के प्रयोजन हेतु हैं.
3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.
4. अतः राज्य शासन एतद्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202111042100047/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लंकापाली प.ह.नं. 37	0.217	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत केलापाली एवं सुलोनी माईनर नहर निर्माण हेतु पूरक भू- अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202111042100048/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसल्दा प.ह.नं. 20	0.371	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत तिलगी माईनर नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202108042100091/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोरा प.ह.नं. 01	0.643	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत अमलडीहा माईनर नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202108042100092/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोरा प.ह.नं. 01	0.049	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत तारापुर माईनर नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2018-19.— भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-छिछौर उमरिया, प.ह.नं.-35 तहसील पुसौर, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.440 हे. केलो परियोजना अंतर्गत छिछौर उमरिया माइनर नहर केलो परियोजना रायगढ़ निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11(1) की अधिसूचना तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 12-04-2019 तथा दिनांक 01-11-2019 को कराया गया है।

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि पूर्व में अर्जन किया जा चुका है। फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है।

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-छिछौर उमरिया

क्र.	ख. नं.	रकबा	क्र.	ख. नं.	रकबा
1.	1703	0.020	2.	369/1	0.006

कुल खसरा - 02 कुल रकबा 0.026 हे.

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 जनवरी 2022

क्रमांक 03/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	खोरसी प.ह.नं. 28	0.121	जल संसाधन सर्वे. एवं बरॉज निर्माण संभाग क्रमांक 02 चांपा.	शिवरीनारायण बरॉज डूबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 10 जनवरी 2022

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	करेकोट प.ह.नं. 04	0.790	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	बिन्ता - सतसपुर से धर्माबेडा मार्ग के कि.मी.1/2-4 इन्द्रावती नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी लोहण्डीगुड़ा/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 10 जनवरी 2022

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	सतसपुर प.ह.नं. 03	0.110	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	बिन्ता – सतसपुर से धर्माबेडा मार्ग के कि.मी.1/2-4 इन्द्रावती नदी पर सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी लोहण्डीगुड़ा/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 जनवरी 2022

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	गढिया प.ह.नं. 18	4.55	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	मुंडीगुडा गढिया व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी लोहण्डीगुड़ा/कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 7 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202107220300025/अ-82/वर्ष 2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	कौन्दकेरा	0.24	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	कौन्दकेरा-खेड़ीटिकरा मार्ग पर सती (ढेका) नाला पर उच्च स्तरीय पुलमय पहुँचमार्ग का निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नम्रता गांधी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

(1)	(2)
621	0.100
622	0.110
620	0.080

जशपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/7423/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-माकरचुवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.264 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.130
29	0.480
17/1	0.020
17/2	0.090
15/1	0.060
15/2	0.120
15/3	0.150
8/1	0.090
8/2	0.100
8/3	0.150
5	0.004
4	0.030
126	0.240
124	0.130
103	0.010
117/1	0.130
117/2	
119	0.030
115	0.010

योग	21	2.264
-----	----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मैनी एनीकेट योजना की मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रितेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

क्रमांक 13/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बेलगहना
- (ग) नगर/ग्राम-नगोई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.575 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
279/2	0.028
282/2	0.134
280	0.020
282/1	0.049

(1)	(2)	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
282/3	0.045		
283/2	0.166		
283/4	0.036	66/1	0.081
283/5	0.036	66/2	0.121
283/6	0.024	67	0.020
283/7	0.036	68	0.089
295	0.308	72/1	0.024
297/1	0.057	72/2	0.162
297/2	0.045		
297/3	0.049		
298	0.073	योग	0.498
300/4	0.032		
299/1,			
299/3,	0.113		
349			
299/2	0.045		
299/4	0.032		
348/5	0.223		
348/4	0.024		
योग	1.575		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगोई-नगपुरा मार्ग में अरपा नदी पर पुल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगोई-नगपुरा मार्ग में अरपा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

महासमुन्द, दिनांक 21 जनवरी 2022

क्रमांक 14/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बेलगहना
(ग) नगर/ग्राम-लमरीडबरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.498 हेक्टेयर

क्रमांक 22 क/कले./भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-सरायपाली
(ग) नगर/ग्राम-पड़कीपाली, प.ह.नं. 50
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	अनुसूची
(1)	(2)	(1) भूमि का वर्णन-
226	0.03	(क) जिला-महासमुन्द
227/1	0.02	(ख) तहसील-सरायपाली
227/2	0.03	(ग) नगर/ग्राम-बटकी, प.ह.नं. 46
228	0.11	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.49 हेक्टेयर
229	0.34	
240	0.04	खसरा नम्बर
243	0.04	रकबा (हेक्टेयर में)
230	0.07	(1) (2)
232/2	0.58	41/1 0.08
236	0.04	41/2 0.01
242	0.04	40 0.02
244	0.21	190 0.02
238	0.07	39 0.22
241	0.19	38 0.04
237	0.04	193 0.18
245	0.02	191/1 0.01
239	0.04	192 0.04
246	0.02	194 0.08
120	0.14	8 0.16
121	0.02	196 0.15
योग	20 2.09	198 0.13
		12 0.10
		10 0.01
		11 0.16
		7 0.08
		योग 17 1.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेन्द्रीनाला-व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21 जनवरी 2022

क्रमांक 23 क/कले./भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोईरमाल-व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21 जनवरी 2022

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

क्रमांक 27 क/कले./भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)

(2)

434

0.12

योग

01

0.12

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-कांकेनचुवां, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमरकोट-व्यपवर्तन योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

क्रमांक/18061/अधीक्षक/2021.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश क्र. 12917/अधीक्षक/2021 कोरबा, दिनांक 13-10-2021 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त सुश्री ममता यादव संयुक्त कलेक्टर कोरबा को आकांक्षी जिला नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 21 जनवरी 2022

क्रमांक/664/अधीक्षक/2022.—प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से श्री एम. एस. कंवर, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी कोरबा को आगामी आदेश पर्यन्त आकांक्षी जिला का सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रानू साहू,
कलेक्टर.

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5823. — कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/4476 रायपुर दिनांक 22-10-2019 द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता, सहायक संचालक को कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त कलेक्टर, वास्ते कलेक्टर राजनांदगांव (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/8982/ज्ये.लि.-1/2021 दिनांक 14-12-2021 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के भारसाधक अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता सहायक संचालक (कृषि) दिनांक 31-10-2021 को सेवानिवृत्त होने से भारसाधक अधिकारी का पद रिक्त होने का उल्लेख करते हुए उनके स्थान पर कृषि विभाग के कृषि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी खैरागढ़ श्री सी.पी. नायक को कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का नाम प्रस्तावित किया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री अशोक कुमार गुप्ता, सहायक संचालक के स्थान पर श्री सी.पी. नायक कृषि वरिष्ठ विकास अधिकारी खैरागढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5979. — कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/1505-1506 रायपुर दिनांक 23-06-2014 द्वारा श्री हरजीत सिंह भल्ला, सहायक संचालक (कृषि) को कृषि उपज मंडी समिति रायपुर जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री हरजीत सिंह भल्ला, सहायक संचालक (कृषि) के स्थान पर श्री यू.एस. अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति रायपुर जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

भुवनेश यादव,
संचालक.

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 12 जनवरी 2022

शुद्धि पत्र

क्रमांक 158/न.ग्रा.नि./नवागढ़ नि.क्षे./2022. — संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग की अधिसूचना क्रमांक 2396 दिनांक 29-03-2017 एवं अधिसूचना क्रमांक 4046 दिनांक 09-04-2018 जो कि क्रमशः “छत्तीसगढ़ राजपत्र” (साधारण) भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 989 दिनांक 16-06-2017 एवं भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 1318-1319 दिनांक 15-06-2018 को मुद्रित हुई है, में लिपिकीय त्रुटिवश ग्रामों के नाम “गंगापुर, कोड़िया, समेशर व गोपाल भैयना” अंकित है, जिन्हें क्रमशः “गांगपुर, कौड़िया, समेशर व गोपाल भोयना” पढ़ा जावे.

विमल बगवैया,
प्र. संयुक्त संचालक.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/3127.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे (1) श्री अब्दुल रज्जाक, (2) मो. अहमद, (3) श्रीमति आमना बेगम, (4) श्रीमति रूमना हुसैन, (5) श्री शेख रहमुद्दीन, (6) श्री अ. नजीर, (7) श्री रेशम लाल जांगड़े, (8) श्री शरीक अल्मास, (9) श्री सुभाष कुर्रे एवं (10) डॉ. गोजूपाल, जिला-रायपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले),
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अब्दुल रज्जाक जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अब्दुल रज्जाक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अब्दुल रज्जाक को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अब्दुल रज्जाक द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अब्दुल रज्जाक ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अब्दुल रज्जाक निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबोधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अब्दुल रज्जाक, नेहरू नगर, चाँदनी चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Abdul Razzak, an Independent contesting candidate from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Abdul Razzak, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Abdul Razzak, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Abdul Razzak, on 03rd July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Sh. Abdul Razzak, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Abdul Razzak, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Abdul Razzak, Neharu Nagar, Chandani Chowk, Raipur, Chhattisgarh and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मो. अहमद जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मो. अहमद को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मो. अहमद को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मो. अहमद द्वारा दिनांक 08 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मो. अहमद ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मो. अहमद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है.

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी मो. अहमद, म.नं.-102, नवीन मार्केट के पीछे, नयापारा, रायपुर को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Md. Ahmad, an Independent contesting candidate from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Md. Ahmad, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Md. Ahmad, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Md. Ahmad, on 08th July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Md. Ahmad, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Md. Ahmad, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Md. Ahmad, H. No. 102, Naveen Market ke Peechhe, Raipur Chhattisgarh and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमति आमना बेगम जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमति आमना बेगम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमति आमना बेगम को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमति आमना बेगम द्वारा दिनांक 08 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमति आमना बेगम ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमति आमना बेगम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है.

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहिंत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्रीमति आमना बेगम, म.नं.-992/1, मथपुरेना टीकारापारा, रायपुर को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहिंत है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Smt. Aamna Begam, an Independent contesting candidate from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Smt. Aamna Begam, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Smt. Aamna Begam, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Smt. Aamna Begam, on 08th July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Smt. Aamna Begam, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Smt. Aamna Begam, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Aamna Begam, H.No. 992/1, Mathpurena Tikarapara, Raipur and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमति रूमना हुसैन जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमति रूमना हुसैन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमति रूमना हुसैन को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमति रूमना हुसैन द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमति रूमना हुसैन ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमति रूमना हुसैन निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्रीमति रूमना हुसैन, म.नं.-38/1040, कालीबाड़ी गांधी चौक, रायपुर को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Smt. Rumana Hussain, an Independent contesting candidate from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Smt. Rumana Hussain, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Smt. Rumana Hussain, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Smt. Rumana Hussain, on 03rd July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Smt. Rumana Hussain, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Smt. Rumana Hussain, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Rumana Hussain, H. No. 38/1040, Kalibadi Gandhi Chowk, Raipur and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री शेख रहमुद्दीन जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शेख रहमुद्दीन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शेख रहमुद्दीन को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री शेख रहमुद्दीन द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शेख रहमुद्दीन ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शेख रहमुद्दीन निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री शेख रहमुद्दीन, म.नं.-38/342, मुस्लिम बस्ती, चाँदनी चौक नेहरू नगर, रायपुर को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Shekh Rahmudoodin, an Independent contesting candidate from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Shekh Rahmudoodin, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Shekh Rahmudoodin, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Shekh Rahmudoodin, on 03rd July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Sh. Shekh Rahmudoodin, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Shekh Rahmudoodin, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Shekh Rahmudoodin, House No. 38/342, Muslim basti, chandini chowk neharu nagar, Raipur and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अ. नजीर जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अ. नजीर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अ. नजीर को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अ. नजीर द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अ. नजीर ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अ. नजीर निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है.

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अ. नजीर, म.नं. 885, शिव नगर, संतोषी नगर, तिकारापारा, रायपुर को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. A. Nazir, an Independent contesting candidate from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. A. Nazir, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. A. Nazir, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. A. Nazir, on 07th July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Sh. A. Nazir, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. A. Nazir, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. A. Nazir, H. No. 885, Shiv Nagar, Santoshi Nagar, Tikarapara, Raipur and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रेशम लाल जांखड़े जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रेशम लाल जांखड़े को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रेशम लाल जांखड़े को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री रेशम लाल जांखड़े द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रेशम लाल जांखड़े ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रेशम लाल जांखड़े निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना के अभ्यर्थी श्री रेशम लाल जांखड़े, म.नं.-12/119, चुना भट्टी, रमन मंदिर, वार्ड-21, रायपुर छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Resham Lal Jangde, a contesting candidate of Shivesena, from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Resham Lal Jangde for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Resham Lal Jangde, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Resham Lal Jangde, on 05th July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Sh. Resham Lal Jangde, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Resham Lal Jangde, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Resham Lal Jangde, H. No. 12/119, Chuna Bhatti, Raman Mandir, ward No. 21, Raipur and an contesting candidate of Shivsena for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री शरीक अल्मास जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शरीक अल्मास को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शरीक अल्मास को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री शरीक अल्मास द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शरीक अल्मास ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शरीक अल्मास निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री शरीक अल्मास, म.नं.-40/266, संजय नगर, आर.डी.ए., टिकरपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Shariq Almas, an Independent contesting candidate from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Shariq Almas for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Shariq Almas, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Shariq Almas, on 03rd July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Sh. Shariq Almas, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Shariq Almas, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Shariq Almas, H. No. 40/266, Sanjay Nagar, RDA, Tikarapara, Raipur and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुभाष कुर्रे जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुभाष कुर्रे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुभाष कुर्रे को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सुभाष कुर्रे द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुभाष कुर्रे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुभाष कुर्रे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री सुभाष कुर्रे, म.नं.-W/47/A/409, डॉ. राजेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Subhash Kurre, an Independent contesting candidate from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Subhash Kurre for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Subhash Kurre, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Subhash Kurre, on 03rd July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Sh. Subhash Kurre, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Subhash Kurre, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Subhash Kurre, H. no. W/47/A/409, Dr. Rajendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसम्बर, 2021—25 अग्रहायण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/51/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री डॉ. गोजूपाल जो छत्तीसगढ़ के 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए डॉ. गोजूपाल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए डॉ. गोजूपाल को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस डॉ. गोजूपाल द्वारा दिनांक 08 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 06 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 460/निर्वा./नि.प./2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि डॉ. गोजूपाल ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि डॉ. गोजूपाल निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अभ्यर्थी डॉ. गोजूपाल, म.नं.-59/1, लक्ष्मी नगर, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16th December, 2021—25 Agrahayana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/51/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 51-Raipur City South Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Dr. Gojupaul, a contesting candidate of Republican Party of India (A), from 51-Raipur City South Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Dr. Gojupaul for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Dr. Gojupaul, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Dr. Gojupaul, on 03rd July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur City South vide his letter No. 460/निर्वा./नि.प./2021 dated 06th August, 2021, has stated that Dr. Gojupaul, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Dr. Gojupaul, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure.

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”,

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Dr. Gojupaul, H. no. 59/1, Laxmi Nagar, Pachpedi Naka, Raipur, Chhattisgarh and a contesting candidate of Republican Party of India (A) for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 51-Raipur City South Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 12923/दो-15-19/2000.—दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य शासन के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित परिवीक्षाधीन सहायक कलेक्टरों को सारणी के स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने दर्शाये गये राजस्व जिले में एक माह (01-02-2022 से 28-02-2022) के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 10 (धारा 181 को छोड़कर), तेरह (धारा 281 और 295-क को छोड़कर), 15 एवं 19 तथा धाराएं 143, 151, 153, 154 से 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-ई, 504, 508, 509 एवं 510 के अधीन दण्डनीय अपराधों, जो एक वर्ष के कारावास से अधिक दण्ड से दण्डनीय न हो, से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्तियों से वेष्टित करता है जो संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विचारण हेतु उन्हें सौंपे जावे.

सारणी

अनु. क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम एवं अधिकृत स्थानीय क्षेत्र (3)
1.	श्री हेमंत रमेश नंदनवार, सहायक कलेक्टर, दुर्ग	दुर्ग
2.	श्री कुमार बिश्वरंजन, सहायक कलेक्टर, बिलासपुर	बिलासपुर

(1)	(2)	(3)
3.	श्री अभिषेक कुमार, सहायक कलेक्टर, रायपुर	रायपुर
4.	श्री प्रतीक जैन, सहायक कलेक्टर, रायगढ़	रायगढ़
5.	सुश्री सुरुचि सिंह, सहायक कलेक्टर, बस्तर	बस्तर स्थान जगदलपुर
6.	सुश्री श्वेता सुमन, सहायक कलेक्टर, सरगुजा	सरगुजा (अंबिकापुर)
7.	सुश्री रोमा श्रीवास्तव, सहायक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा

Bilaspur, the 20th December 2021

No. 12923/II-15-19/2000.—In exercise of the powers Conferred by Section 13(1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and on the request of the State Government of Chhattisgarh, the High Court of Chhattisgarh here-by Confers the powers of Judicial Magistrate of Second Class upon the Probationary Assistant Collectors, whose name are mentioned in column (2) of the table below to exercise jurisdiction in the local areas specified against their respective names in column (3) of the table below for one month (01-02-2022 to 28-02-2022) and to such cases & such offences as may be assigned to them by the Chief Judicial Magistrate of the respective areas under chapters 10 (Except Section 181), 13 (Except Sections 281, 295-A) 15 and 19 and Sections 143, 151, 153, 154, to 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-E, 504, 508, 509 and 510 of the Indian Penal Code, provided that the offences are not punishable with imprisonment for more than one year.

TABLE

Sl. No.	Name of Officer/s	Name of District and Name of Local area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Hemant Ramesh Nandanvar, Assistant Collector, District-Durg.	Durg
2.	Shri Kumar Bishwaranjan, Assistant Collector, District-Bilaspur.	Bilaspur
3.	Shri Abhishek Kumar, Assistant Collector, District-Raipur.	Raipur
4.	Shri Prateek Jain, Assistant Collector, District-Raigarh	Raigarh
5.	Sushri Suruchi Singh, Assistant Collector, District-Bastar.	Bastar at Jagdalpur
6.	Sushri Shweta Suman, Assistant Collector, District-Surguja at Ambikapur.	Surguja at Ambikapur
7.	Sushri Roma Shrivastava, Assistant Collector, District-Janjgir-Champa.	Janjgir-Champa

By order of the High Court,
SANJAY KUMAR JAISWAL, Registrar General.

Bilaspur, the 23rd December 2021

No. 46/L.G./2021/II-3-4/2014.—Shri Hemant Saraf, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 17 days from 09-05-2021 to 25-05-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Saraf, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 238 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 23rd December 2021

No. 47/L.G./2021/II-2-38/2018.—Shri Shahabuddin Qureshi, I/c Registrar (Computerization)-Cum-Central Project Co-ordinator, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted leave for 03 days from 13-12-2021 to 15-12-2021 along with permission to leave headquarters from the evening of 10-12-2021 till the evening of 15-12-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 218 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 23rd December 2021

No. 48/L.G./2021/II-2-8/2021.—Shri Rajeev Kumar, Special Judge (Atrocities), Korba is hereby, granted earned leave for 05 days from 06-12-2021 to 10-12-2021 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 04-12-2021 till before the Court hours of 13-12-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajeev Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 23rd December 2021

No. 49/L.G./2021/II-2-25/2016.—Shri Arvind Kumar Sinha, District & Sessions Judge, Mungeli is hereby, granted earned leave for 13 days from 22-11-2021 to 04-12-2021 along with permission to remain out of headquarters from 19-11-2021 to 05-12-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sinha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 242 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 23rd December 2021

No. 50/L.G./2021/II-2-14/2015.—Shri Sudhir Kumar, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 02 days on 13-12-2021 & 14-12-2021 along with permission to remain out of headquarters from the morning of 12-12-2021 till the evening of 14-12-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 173 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 23rd December 2021

No. 51/L.G./2021/II-3-3/2011.—Shri Rajnish Shrivastava, District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 02 days on 22-11-2021 to 23-11-2021 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 18-11-2021 till before the Court hours of 24-11-2021 and earned leave for 01 day on 04-12-2021 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 03-12-2021 till before the Court hours of 06-12-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By Order of the High Court,
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)
